गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 224
दि. 15.12.2025,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

हनुक्का की रोशनी में दहशत का साया: सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला, 12 लोगों की मौत से दुनिया स्तब्ध

(जीएनएस)। सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित बॉन्डी बीच पर रविवार को हुए भीषण आतंकी हमले ने न केवल ऑस्ट्रेलिया, बल्कि पूरी दुनिया को गहरे सदमे में डाल दिया। हनुक्का पर्व के अवसर पर यहूदी समुदाय द्वारा आयोजित समारोह उस समय खून और चीख-पुकार में बदल गया, जब ऑटोमैटिक हथियारों से लैस आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस बर्बर हमले में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 29 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में दो पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज अस्पताल में जारी है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमले के वक्त बॉन्डी बीच पर करीब एक हजार लोग हनुक्का उत्सव में शामिल थे। चारों ओर संगीत, प्रार्थना और उत्सव का माहौल था, तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। कुछ ही पलों में खुशियों से भरा यह आयोजन अफरातफरी में बदल गया। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, कई जमीन पर लेट गए और कई समुद्र की ओर दौड़ पड़े। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और एक हमलावर को मौके पर ही मार गिराया, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में गिरफ्तार कर लिया गया।

न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर मैल लैन्योन ने इस घटना को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी हमला घोषित किया है। उन्होंने बताया कि मारे गए आतंकी

की कार से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी भी बरामद की गई है, जिसके बाद पूरे इलाके को घेरकर बम निरोधक दस्ते को तैनात कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की गहन जांच कर रही हैं कि कहीं इस हमले में कोई तीसरा आतंकी तो शामिल नहीं था। बॉन्डी बीच और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। इस हमले में यहूदी समुदाय के प्रमुख नेता आर्सेन ऑस्ट्रोव्स्की के घायल होने की खबर ने चिंता और बढ़ा दी है। उनके सिर में गोली लगी है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आर्सेन वही व्यक्ति हैं जो 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास हमले में चमत्कारिक रूप से बच गए थे। अस्पताल से दिए गए बयान में उन्होंने बताया कि गोलियां अचानक चलने लगीं और लोग अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर लेट गए। उन्होंने इस हमले को मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। जांच के दौरान हमले के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की आशंका भी सामने आई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, कथित हमलावरों में से एक की पहचान 24 वर्षीय नवीद अकरम के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला बताया जा रहा है। सिडनी में उसके ठिकाने पर छापा मारा गया है और अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से उसके संबंधों की गहन जांच की जा रही है। हालांकि, जांच एजेंसियों ने अभी इस संबंध में अंतिम पुष्टि नहीं की है।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने इस हमले को यहूदियों के खिलाफ कायराना और घृणित आतंकी कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि नफरत और हिंसा के लिए ऑस्ट्रेलिया में कोई स्थान नहीं है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने भी लोगों से शांति और एकता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि आतंक का जवाब एकजुट होकर ही दिया जा सकता है।

इस दर्दनाक घटना पर वैश्विक स्तर पर शोक की लहर दौड़ गई है। भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, इजराइल, पाकिस्तान, क़तर, यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इस दुख की घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूती से खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे शांति और रोशनी के पर्व पर किया गया भयावह हमला बताया, जबकि यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यहूदी-विरोध और हिंसा के खिलाफ पूरा यूरोप एकजुट है। ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के नेताओं ने भी पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।

फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही हैं। देशभर में यहूदी धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक आयोजनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉन्डी बीच पर हुआ यह आतंकी हमला न केवल ऑस्ट्रेलिया की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह संदेश भी है कि आतंक और नफरत के खिलाफ सतर्कता और एकजुटता पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है।

इंदौर को मिलेगा प्रदेश का सबसे बड़ा चिकित्सा तोहफा, 773 करोड़ की लागत से बनेगा 1450 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक अस्पताल

(जीएनएस)। इंदौर। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में इंदौर में एक ऐतिहासिक पहल की गई है। महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय यानी एमवाय अस्पताल परिसर में 773.07 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 1450 बिस्तरों के अत्याधुनिक अस्पताल का भूमि पूजन रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। इस मौके पर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इस परियोजना को न केवल इंदौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा के नेतृत्व में देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है और मध्य प्रदेश भी उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इंदौर प्रदेश का गौरव है और एमवाय अस्पताल की पहचान सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं, बल्कि आसपास के राज्यों तक है। नए अस्पताल के निर्माण से इंदौर के साथ-साथ सीमावर्ती जिलों और पड़ोसी राज्यों से आने वाले मरीजों को भी विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे उन्हें बड़े महानगरों की ओर भटकना नहीं पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग को एकीकृत कर व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया है, ताकि इलाज, प्रशिक्षण और शोध के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि एमवाय अस्पताल में पहले से ही बोनमैरो और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी जटिल और महंगी चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। उन्होंने निर्माण एजेंसी को सख्त निर्देश दिए कि गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए और परियोजना को तय समयसीमा में पूरा किया जाए।

नए अस्पताल भवन में अत्याधुनिक चिकित्सा ढांचे के साथ विभिन्न विभागों के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। मेडिसिन और सर्जरी विभाग में 330-330 बिस्तरों की सुविधा होगी, जबकि ऑर्थोपेडिक्स विभाग में 180 बिस्तर रखे गए हैं। शिशु रोग सर्जरी के लिए 60 और सामान्य शिशु रोग वार्ड के लिए 100 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। न्यूरो सर्जरी में 60, ईएनटी में 30, दंत रोग और त्वचा रोग विभाग में 20-20 बिस्तर होंगे। मातृ एवं शिशु वार्ड में 100, नेत्र वार्ड में 80 और इमरजेंसी मेडिसिन के लिए 180 बिस्तर प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे आपातकालीन स्थितियों में मरीजों को तुरंत और बेहतर इलाज मिल सके। इस विशाल चिकित्सा परिसर को आत्मनिर्भर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की भी योजना है। परिसर में 550 बिस्तरों वाला नर्सिंग हॉस्टल बनाया जाएगा, ताकि नर्सिंग स्टाफ को बेहतर आवासीय सुविधा मिल सके। इसके अलावा 250 सीटों वाला मिनी ऑडिटोरियम, पर्याप्त सार्वजनिक पार्किंग, सोलर पैनल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और आधुनिक जल आपूर्ति प्रणाली भी विकसित की जाएगी। इन सुविधाओं के जरिए अस्पताल को आधुनिक, स्वच्छ और टिकाऊ मॉडल के रूप में तैयार किया जाएगा।

यह परियोजना इंदौर को न केवल मध्य प्रदेश बल्कि मध्य भारत के प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस अस्पताल के शुरू होने के बाद इलाज के लिए बाहर जाने वाले मरीजों की संख्या में भारी कमी आएगी और इंदौर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाएगा। सरकार का यह प्रयास प्रदेश के आम नागरिक को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को भी मजबूती से दर्शाता है।

दिल्ली की रैली पर बीजेपी का पलटवार, अनिल विज बोले-लगातार हार से घबराई कांग्रेस कर रही 'वोट चोर गद्दी छोड़' की तेरहवीं

(जीएनएस)। चंडीगढ़। वोट चोरी के आरोपों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस द्वारा आयोजित भव्य रैली पर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने इस रैली को लेकर कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस की इस पहल को राजनीतिक हताशा का परिणाम बताते हुए कहा कि लगातार चुनावी हार से परेशान कांग्रेस अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हर बार नया बहाना ढूंढ लेती है और अब 'वोट चोर गद्दी छोड़' की तेरहवीं कर रही है। अनिल विज के इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है।

अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में हाल के वर्षों में जहां-जहां चुनाव हुए हैं, वहां कांग्रेस को जनता ने नकारा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कभी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करती है तो कभी चुनाव आयोग पर उंगली उठाती है, लेकिन आज तक यह नहीं बता पाई कि आखिर वोट चोरी हुई कैसे और किसने की। विज ने कहा कि जब भी चुनाव में हार होती है, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने लगती है। उनके अनुसार यह कांग्रेस की पुरानी आदत बन चुकी है, जो अब जनता के सामने भी साफ दिखाई देने लगी है।

मंत्री विज ने कांग्रेस को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि जिन मतदाता सूचियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़े और जीत दर्ज की, वही मतदाता सूचियां कांग्रेस उम्मीदवारों के पास भी थीं। अगर कांग्रेस का यह दावा है कि मतदाता सूचियां गलत थीं या उनमें गड़बड़ी थी, तो उसे सबसे पहले अपने उन विधायकों से इस्तीफा लेना चाहिए जो उन्हीं सूचियों के आधार पर चुनाव जीतकर विधानसभा या संसद पहुंचे हैं। इसके बाद ही कांग्रेस को दिल्ली में रैली करने का नैतिक अधिकार होगा। विज ने कहा कि दोहरे मापदंड अपनाकर कांग्रेस जनता को गुमराह नहीं कर सकती।

इस पूरे मुद्दे पर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो पार्टी वर्षों से ईवीएम को हैक बताती रही है, वही अब वोट चोरी के नाम पर रैली कर रही है। जाखड़ ने तंज कसते हुए पूछा कि अगर ईवीएम पहले से ही हैक हैं, तो फिर वोट चोरी करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। उनके मुताबिक कांग्रेस खुद यह तय नहीं कर पा रही है कि उसकी हार का बहाना ईवीएम है या वोट चोरी।

सुनील जाखड़ ने आगे कहा कि कांग्रेस की स्थिति अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसके अपने कार्यकर्ता भी पार्टी के इन आरोपों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़ने वाली नीतियों की कमी, संगठनात्मक कमजोरी और नेतृत्व पर घटता विश्वास ही कांग्रेस की हार के असली कारण हैं, लेकिन पार्टी इन मुद्दों पर आत्ममंथन करने के बजाय सड़कों पर उतरकर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है।

बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की यह रैली जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश है, लेकिन अब लोग पहले से ज्यादा जागरूक हैं और ऐसे आरोपों को गंभीरता से नहीं ले रहे। दिल्ली की रैली को लेकर शुरू हुई यह बयानबाजी आने वाले दिनों में और तेज होने के संकेत दे रही है, क्योंकि चुनावी माहौल के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है।

स्टेडियम में मेसी कार्यक्रम के बाद हुई तोड़फोड़, ऑर्गनाइजर सतादु दत्ता की जमानत अर्जी खारिज

(जीएनएस)। कोलकाता। लियोनेल मेसी के इवेंट के दौरान स्टेडियम में हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में ऑर्गनाइजर सतादु दत्ता को रविवार को बिधाननगर सब-डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में उनके वकील ने दलील दी कि कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया था, लेकिन स्टेडियम में जो अफरातफरी हुई, उसकी जिम्मेदारी कैसे उनके सिर डाली जा सकती है। उनका कहना था कि उन्होंने कोई सरकारी संपत्ति नहीं तोड़ी और उनके खिलाफ MPO (मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर) एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, जबकि वे केवल इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे थे।

सरकारी वकील अमिताभ लाला ने कोर्ट में जवाब दिया कि इस तरह के कार्यक्रमों में यह ऑर्गनाइजर की जिम्मेदारी होती है कि तय किया जाए कि मेसी के सामने कौन जाएगा और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि दत्ता ने अपने सुरक्षा और व्यवस्थापकीय इंतजामों में ऐसी व्यवस्था बनाई कि आम दर्शक स्टार को ठीक से नहीं देख पाए और इसी वजह से अफरा-तफरी और तोड़फोड़ हुई।

सतादु दत्ता के वकील ने कोर्ट में यह भी कहा कि उनका क्लाइंट मेसी को राज्य में एक बड़े मकसद से लाए थे ताकि युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को उनसे सीखने का अवसर मिले। वकील का तर्क था कि एक इवेंट मैनेजर और एक ऑर्गनाइजर का काम अलग होता है और उनके क्लाइंट को शिकार बनाया गया है।

कोर्ट ने ऑर्गनाइजर की जमानत अर्जी खारिज कर दी और 14 दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर की। अदालत ने यह भी नोट किया कि सतादु दत्ता और उनके सहयोगियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाई कि दर्शक असंतुष्ट हुए और हिंसा की स्थिति उत्पन्न हुई।

स्टेडियम के बाहर वकील ने मीडिया से कहा कि उनके क्लाइंट घटनास्थल के पास ही रहेंगे और पुलिस कस्टडी की अवधि को कम करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। यह मामला अब जांच के अधीन है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

इस घटना ने इवेंट मैनेजमेंट और सुरक्षा व्यवस्था के महत्व को फिर से उजागर किया है, जहां हजारों दर्शक और स्टार खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आयोजकों की मुख्य जिम्मेदारी बनती है।

साइबर ठगी के अंधेरे साम्राज्य पर बड़ी चोट, जूनागढ़ पुलिस ने 253 करोड़ के फ्रॉड नेटवर्क का किया भंडाफोड़

(जीएनएस)। जूनागढ़। देशभर में तेजी से फैलते साइबर अपराध के खिलाफ जूनागढ़ साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई करते हुए 253 करोड़ के विशाल साइबर फ्रॉड रैकेट का खुलासा किया है। 'ऑपरेशन म्यूल हंट' के तहत की गई इस कार्रवाई में अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अहम आरोपी पहले से सूरत जेल में बंद है, जिसे पूछताछ के लिए जूनागढ़ लाने की तैयारी चल रही है। इस कार्रवाई के बाद साइबर ठगी के उस संगठित नेटवर्क की कई परतें सामने आई हैं, जो देश के अलग-अलग हिस्सों में फैलकर आम लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहा था। पुलिस के अनुसार इस साइबर फ्रॉड नेटवर्क में शामिल आरोपियों ने बेहद सुनियोजित तरीके से सैकड़ों म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल किया। जांच में सामने आया है कि करीब 360 से अधिक बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपये की अवैध हेराफेरी की गई। इन खातों का उपयोग फर्जी ट्रांजैक्शन, रकम को इधर-उधर घुमाने और लेयरिंग के जरिए असली स्रोत छिपाने के लिए किया जाता था। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक समेत कई बड़े बैंकों के खातों में संदिग्ध लेनदेन पाए गए हैं, जिससे यह साफ हो गया कि गिरोह का नेटवर्क काफी बड़ा और संगठित था।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पवन हिरानी, जावेद तुर्क, भरत देत्रोंजा, एरजन गरेजा, अल्ताफ समा, सोनू सोढा, चिराग साधु और रक्षित काछडिया शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि इन सभी की भूमिका अलग-अलग स्तर पर थी। कोई म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराता था, तो कोई रकम की ट्रांसफर चेन को संभालता था। वहीं हुसैन तुर्क नाम का आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

साइबर क्राइम पुलिस अधिकारी सी. वी. नायक ने बताया कि यह पूरी जांच गुजरात सरकार के समन्वय पोर्टल से मिले इनपुट के बाद शुरू की गई। सरकार की ओर से निर्देश मिले थे कि साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल हो रहे म्यूल बैंक खातों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद तकनीकी निगरानी, बैंक डाटा एनालिसिस और ट्रांजैक्शन पैटर्न की गहन जांच की गई, जिससे इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस ने डिजिटल सबूतों के आधार पर एक-एक कड़ी जोड़ते हुए आरोपियों तक पहुंच बनाई।

इस मामले में एक आरोपी पहले से ही सूरत जेल में बंद है, जिसे इस गिरोह का अहम सदस्य माना जा रहा है। पुलिस ने उसे ट्रांसफर ऑर्डर के जरिए जूनागढ़ लाकर पूछताछ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का मानना है कि उससे पूछताछ के बाद इस साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े कई और नाम सामने आ सकते हैं और ठगी के नए तरीकों का भी खुलासा हो सकता है।

फिलहाल पुलिस सभी 360 बैंक खातों की बारीकी से जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किन-किन लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया और पैसे की अंतिम मंजिल कहां थी। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जूनागढ़ पुलिस की इस कार्रवाई को साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिसने यह साफ संदेश दे दिया है कि डिजिटल ठगी करने वालों के लिए अब कानून का शिकंजा और ज्यादा सख्त होने वाला है।

संपादकीय

उच्च शिक्षा में सुधार की योजना, अमल की धीमी रफ्तार बनेगी चुनौती

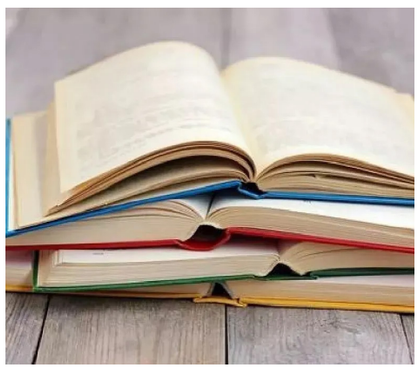

शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी बनाने की योजना पर जो काम कर रहा है, वह सही तो है, लेकिन केवल इतने भर से बात बनने वाली नहीं है। उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ ही उनकी शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर भी बढ़ना चाहिए। यह ठीक है कि नई शिक्षा नीति के तहत इस दिशा में कई प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन एक तो उन पर अमल की गति बहुत धीमी है और दूसरे चुनिंदा शिक्षा संस्थानों में ही सुधार हो पा रहा है।

उच्च शिक्षा के समक्ष जैसी चुनौतियां हैं और विशेष रूप से देश को जैसे सक्षम युवाओं की आवश्यकता है, उसे देखते हुए कुछ नए और ठोस उपायों पर शीघ्रता से काम किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा संस्थानों से ऐसे युवा निकलने चाहिए, जो उद्योग-व्यापार जगत की आवश्यकता पूरी करने में सक्षम हों। यह ठीक नहीं कि उच्च शिक्षा संस्थानों से निकले तमाम छात्र केवल शिक्षित बेरोजगारों की भीड़ बढ़ाएं।

इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि देश में सरकारी के साथ निजी स्तर पर भी उच्च शिक्षा के तमाम संस्थान खुलते चले जा रहे हैं, क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि छात्रों को आज की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम नहीं उपलब्ध कराया जा पा रहा है। निःसंदेह इसके चलते भी बड़ी संख्या में हमारे छात्र विदेश पढ़ने चले जाते हैं। उनमें से कम ही देश लौटते हैं।

एक समस्या यह भी देखने को मिल रही है कि शिक्षा संस्थानों में योग्य शिक्षकों का अभाव व्याप्त हो रहा है। उच्च शिक्षा के कई शिक्षण संस्थान ऐसे भी हैं, जिनमें पर्याप्त संख्या में शिक्षक ही नहीं हैं। दुर्भाग्य से सरकारी शिक्षण संस्थानों में भी यह स्थिति देखने को मिल रही है। यह सामान्य बात नहीं कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों तक में शिक्षकों के पद खाली हैं।

राज्य स्तर के विश्वविद्यालयों की स्थिति भी अच्छी नहीं। इसी तरह व्यावसायिक शिक्षा के संस्थानों में भी शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा? पिछले कुछ समय से विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने केंद्र खोल रहे हैं। हो सकता है कि इसके चलते भारत के छात्रों के विदेश पढ़ने जाने का सिलसिला कुछ थमे, लेकिन आखिर हमारे अपने शिक्षा संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं?

एक प्रश्न यह भी है कि जो प्रतिष्ठित और बड़े शिक्षण संस्थान हैं, वे अन्य शिक्षण संस्थाओं में पठन-पाठन की गुणवत्ता सुधारने में कोई सहयोग क्यों नहीं दे सकते? यदि देश भर के छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना पसंद करते हैं तो इसका मतलब है कि सभी राज्यों में उच्च शिक्षा के अच्छे संस्थान नहीं हैं।

शिक्षा में चमके नया सूरज, भारतीय ज्ञान की रोशनी में लिखा जाएगा भविष्य

> स्वतंत्रता के बाद भी, शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित रही, लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषाओं को शिक्षा की मूल भाषा बनाने पर केंद्रित है। यह नीति शिक्षा को रटने की बजाय कौशल और समझ पर आधारित करने का प्रयास करती है, और भारतीय ज्ञान को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है।

वर्ष 1835 में जब थामस बैबिंगटन मैकाले ने अपना प्रसिद्ध 'मिनट आन एजुकेशन' लिखा, तब शायद उसे भी अनुमान नहीं था कि इसकी कुछ पंक्तियां सदियों तक भारत की शिक्षा-संरचना, भाषा-विचार और मानसिकता को इस गहराई तक प्रभावित करेंगी, लेकिन हुआ यही। एक छोटे से नोट ने भारत की विशाल और बहुभाषी शिक्षा परंपरा को झकझोर कर रख दिया। ब्रिटिश शासन से पहले भारत में शिक्षा स्वाभाविक, स्थानीय और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई थी। गुरुकुल, पाठशालाएं, गुरु-शिष्य परंपरा, वैदिक-गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा, तर्क-शास्त्र-सब भारतीय भाषाओं में पनपे।

बच्चा अपनी भाषा में सोचता था, सीखता था और जीवन-ज्ञान अर्जित करता था। ज्ञान केवल पुस्तकों एवं पांडुलिपियों तक सीमित नहीं था, यह जीवन और संस्कृति का हिस्सा था। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में शिक्षा में रुचि नहीं रखती थी, परंतु धीरे-धीरे अंग्रेजों को यह समझ आया कि भारत जैसा विशाल देश केवल ताकत से नहीं, बल्कि शिक्षा एवं संस्कृति को बदलकर ही चलाया जा सकता है। यहीं से शुरू हुई भारतीय समाज को अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी सोच के दायरे में ढालने की नीति। मैकाले ने साफ लिखा कि पश्चिमी साहित्य और विज्ञान सर्वोच्च हैं और भारतीय ग्रंथ-परंपराएं 'कमतर'।

इसमें कहा गया कि सरकार का लक्ष्य ऐसा वर्ग तैयार करना होना चाहिए 'जो रक्त और रंग से भारतीय हो, किंतु विचारों और रुचियों से अंग्रेज।' अंग्रेज जानते थे कि स्थानीय भाषाओं

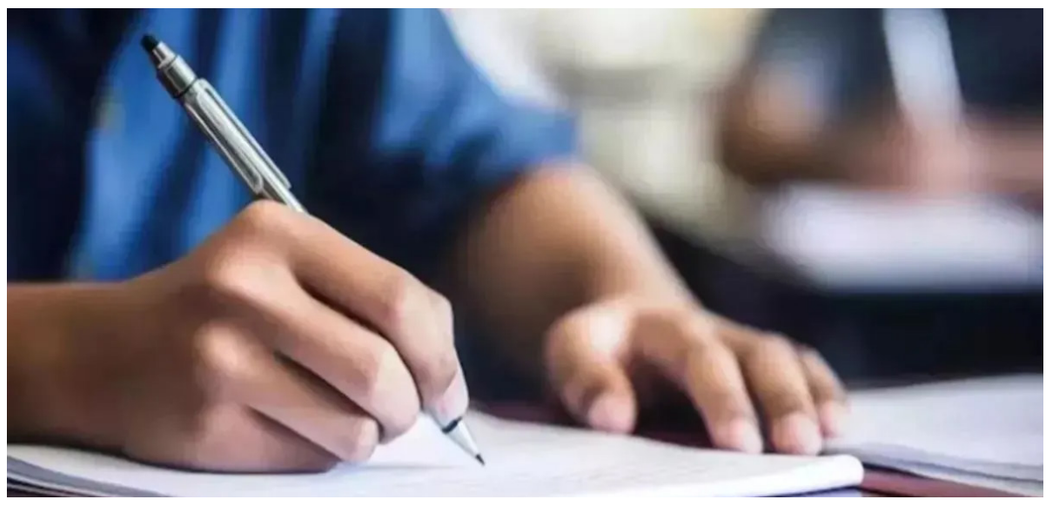

में दी गई शिक्षा भारतीय समाज को एकजुट रखती है। इसलिए अंग्रेजी को आधुनिक और श्रेष्ठ घोषित किया गया तथा भारतीय भाषाओं को धीरे-धीरे प्रशासन, न्यायपालिका और उच्च शिक्षा से दूर किया गया। अंग्रेजी उच्च शिक्षा की एकमात्र सीढ़ी बन गई और भारतीय भाषाएं केवल 'घर-परिवार की भाषा' कहकर पीछे धकेल दी गईं।

देश स्वतंत्र हुआ पर जिस शिक्षा व्यवस्था को हमने विरासत में पाया, वह पूरी तरह ब्रिटिश माडल पर आधारित थी। नीति-निर्माता स्वयं उसी औपनिवेशिक ढांचे में पढ़कर आए थे। कई लोग इंग्लैंड, यूरोप या भारत के अंग्रेजी माडल वाले विश्वविद्यालयों के उत्पाद थे। इस कारण, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा सुधार की दिशा तो बदली, पर संरचना और विचार वही रहे। यह प्रभाव इतना गहरा था कि आज भी कई परिवार अंग्रेजी माध्यम को 'बेहतर जीवन' का प्रतीक मानते हैं। स्वतंत्रता के बाद बड़े आयोग बने-पर दृष्टिकोण यूरोपीय माडल का ही रहा। यह सिलसिला 1948 की राधाकृष्णन समिति, 1964-66 के कोठारी आयोग, 1968 और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां और 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग तक चलता रहा। इन सबके द्वारा शिक्षा में कुछ सुधार तो किया गया, पर ढांचा वही रहा- परीक्षा-केंद्रित, अंग्रेजी-प्रधान और पश्चिमी अकादमिक संरचना की नकल करने वाली शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद स्थापित कई विश्वविद्यालय, जिनमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं, ने ब्रिटिश और यूरोपीय विश्वविद्यालय माडल से आकार पाए।

कुछ भारतीय भाषाएं यहां भी 'अध्ययन का विषय' तो बन सकीं, पर 'ज्ञान की भाषा' नहीं। अंग्रेजी आधारित शिक्षा के कारण भारतीय भाषाएं, विशेषतः संस्कृत, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, धीरे-धीरे उच्च शिक्षा में निम्नतम स्तर पर चलती चली गईं। 1991 के बाद शिक्षा में निजी क्षेत्र के प्रवेश ने अंग्रेजी शिक्षा को और तेजी से बढ़ावा दिया। निजी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम को प्रतिष्ठा का प्रतीक बनाया गया। सरकारी स्कूल भारतीय भाषाओं तक सीमित हो गए। यह वही मानसिकता है जिसकी जड़ें मैकाले की नीति में थीं।

नई शिक्षा नीति 2020 पहली नीति है जिसने कहा कि भारतीय भाषाएं शिक्षा की मूल भाषा हों, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा मिले, भारत का ज्ञान-दर्शन, कला, गणित, साहित्य मुख्य धारा में आए, शिक्षा कौशल और समझ पर आधारित हो, न कि रटने पर। इसमें सामने आया 5+3+3+4 का नया ढांचा, जो भारतीय बचपन, सीखने की प्रकृति और भाषा-मनोविज्ञान से मेल खाता है।

उच्च शिक्षा में बहुविषयक विश्वविद्यालयों का विचार गुरुकुल और तक्षशिला की परंपरा जैसा है। भारतीय शिक्षा अपनी जड़ों की ओर लौट रही है और भारतीय मन औपनिवेशिक छाया से बाहर आने की तैयारी कर रहा है। यह राष्ट्रीय पुनर्जागरण का संकेत है- जहां शिक्षा भारतीय होगी, भाषा भारतीय होगी और भविष्य भारतीय ज्ञान की रोशनी में लिखा जाएगा। 5+3+3+4 ढांचा पारंपरिक 10+2 प्रणाली को बदलकर स्कूली शिक्षा को चार चरणों में बांटता है: 5 साल का फाउंडेशन स्टेज (3 साल प्री-स्कूल + कक्षा 1-2), 3 साल का प्रारंभिक स्टेज (कक्षा 3-5), 3 साल का मध्य स्टेज (कक्षा 6-8) और 4 साल का माध्यमिक स्टेज (कक्षा 9-12) लक्ष्य बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए समग्र और व्यावहारिक शिक्षा देना है, जिसमें तीन साल की उम्र से ही संरचित शिक्षा शुरू होती है।

प्रेरणा

स्मृतियों, प्रकृति और पीड़ा का काव्यात्मक दस्तावेज है

प्रकृति प्रेमी कवि रमेश पठानिया का सद्यः प्रकाशित कविता-संग्रह 'एक नदी का न होना' केवल कविताओं का संकलन नहीं, बल्कि स्मृतियों, संवेदनाओं और पर्यावरणीय चिंता से उपजा एक गहन काव्यात्मक चिंतन है। इस संग्रह का केंद्रीय बिंब हिमाचल प्रदेश की कुल्लू उपत्यका में बहने वाली व्यास नदी है, जो कवि की दृष्टि में अब केवल एक भौगोलिक उपस्थिति नहीं रह गई, बल्कि धीरे-धीरे लुप्त होते जीवन, स्मृति और संस्कृति का प्रतीक बन चुकी है। कवि नदी के 'न होने' की बात करता है, लेकिन यह न होना अचानक नहीं, बल्कि विकास, अतिक्रमण और मानवीय लापरवाही के कारण धीरे-धीरे घटित होती एक त्रासदी के रूप में सामने आता है, जिसे कवि पूरी संवेदनशीलता के साथ दर्ज करता है।

रमेश पठानिया के पूर्व प्रकाशित कविता-संग्रहों की तरह इस पुस्तक में भी प्रकृति अपने विविध रूपों में उपस्थित है। पेड़-पौधे, पहाड़, घाटियां, बदलता मौसम और बीते समय की स्मृतियां कविताओं में बार-बार लौटती हैं, लेकिन इस बार व्यास नदी के प्रति कवि की चिंता अधिक तीव्र और मुखर दिखाई देती है। यह चिंता केवल भावनात्मक नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक स्पष्ट चेतावनी और आग्रह भी छिपा है। कवि को लगता है कि जिस नदी ने सदियों से कई भूभागों को जीवन दिया, वही आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इसलिए वह यह इच्छा भी प्रकट करता है कि व्यास नदी को देश की धरोहर के रूप में मान्यता मिले, ताकि उसके संरक्षण की जिम्मेदारी केवल स्थानीय नहीं,

बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर तय हो सके।

संग्रह में 2023 में बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पृष्ठभूमि भी उभरकर आती है, जिनके कारण हिमालयी क्षेत्रों में नदियों का स्वाभाविक प्रवाह बाधित हुआ है और उनका स्वरूप बदलता जा रहा है। कवि इस तथ्य को अनदेखा नहीं करता कि विकास के नाम पर नदियों का अतिक्रमण हो रहा है, उनके किनारे संकुचित किए जा रहे हैं और उनके स्वभाव से छेड़छाड़ की जा रही है। इसका दुष्प्रभाव अब केवल प्रकृति तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि मानव जीवन भी इसकी कीमत चुका रहा है। कवि की दृष्टि में यह स्थिति केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक संकट भी है।

रमेश पठानिया नदियों और स्त्रियों के बीच एक गहरा साम्य स्थापित करते हैं। उनका मानना है कि जैसे स्त्रियां अत्याचार को लंबे समय तक सहती हैं और फिर उसका प्रतिकार करती हैं, वैसे ही नदियां भी मानवीय हस्तक्षेप और शोषण का बदला सूद समेत लेती हैं। यह विचार संग्रह में एक तीखे बिंब के रूप में उभरता है, जो पाठक को भीतर तक झकझोर देता है। कवि जब नदी के न होने की कल्पना करता है, तो वह केवल जल के अभाव की नहीं, बल्कि स्मृतियों, कला और सौंदर्य के लुप्त हो जाने की कल्पना करता है। वह लिखता है कि जब वह निकोलस रोरिक की पेंटिंग्स, घाटी के किनारों और पूरी वादी को पल भर के लिए बिना नदी के देखता है, तो भीतर से शून्य हो जाता है। यह शून्य केवल दृश्य का नहीं, बल्कि अस्तित्व का शून्य है।

शायद इसी पीड़ा से उपजकर कवि 'नदी को देखो' जैसी कविताओं के माध्यम से पाठक को रुककर, ठहरकर और गंभीरता से सोचने का आह्वान करता है। वह नदी को केवल देखने की नहीं, बल्कि समझने, महसूस करने और उसके साथ अपने संबंध को पहचानने की बात करता है। संग्रह में नदी केवल पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि एक जीवित पात्र की तरह उपस्थित है, जो बोलती है, सहती है और चेतावनी देती है। व्यास नदी के प्रति कवि के हृदय में उपजे ये भाव पूरे संग्रह में बिखरे हुए हैं और मिलकर एक ऐसी काव्य-धारा रचते हैं, जो पाठक को प्रकृति के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है।

इस तरह 'एक नदी का न होना' स्मृतियों का काव्यात्मक दस्तावेज बन जाता है, जिसमें व्यक्तिगत अनुभव, सामूहिक चिंता और भविष्य की आशंका एक साथ गूंथी हुई है। यह संग्रह न केवल कविता प्रेमियों के लिए, बल्कि उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जो यह समझना चाहते हैं कि नदियों का सूखना केवल जल का सूखना नहीं, बल्कि जीवन, संस्कृति और स्मृति का धीरे-धीरे लुप्त हो जाना है।

नियम-कानूनों की घातक अनदेखी, हर घटना के बाद सख्ती दिखाने की होती है कोशिश

गोवा के एक नाइट क्लब में लगी आग ने एक बार फिर सार्वजनिक एवं निजी इमारतों समेत हर जगह सुरक्षा की अनदेखी की पोल खोलकर रख दी। यह पहली बार नहीं है, जब किसी इमारत में आग लगने से लोगों की जानें गई हों। देश में रह-रह कर ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं और बड़ी संख्या में लोग उनमें मरते भी रहते हैं। ऐसी हर घटना के बाद सुरक्षा संबंधी कमियां बड़े पैमाने पर उजागर होती हैं। गोवा नाइट क्लब के मामले में भी उजागर हो रही हैं।

उन्हें गिनाते हुए नाइट क्लब पर बुलडोजर चला दिया गया और उसके संचालकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह की कार्रवाई करते हुए यही संदेश देने की कोशिश की जाती है कि शासन-प्रशासन सख्त है और वह ऐसी कार्रवाई कर रहा हो, जो नजीर बनेगी, लेकिन ऐसा कठिनाई से ही होता है, क्योंकि एक तो कार्रवाई एक सीमा तक ही होती है और दूसरे अनदेखी के लिए जिम्मेदार अधिकारी सजा से बच जाते हैं।

वे ज्यादा से ज्यादा कुछ समय के लिए निलंबित होते हैं। नतीजा यह होता है कि बार-बार वैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, जैसी गोवा में देखने को मिली और जिसमें 25 लोगों की जान चली गई। इतनी अधिक जानें इसीलिए गईं, क्योंकि नाइट क्लब में आग से बचाव के कोई उपाय नहीं थे।

वैसे तो कोई इमारत ऐसी नहीं हो सकती, जिसमें आग लगने की आशंका न रहे, लेकिन भारत में आमतौर पर निजी और सार्वजनिक भवनों में सुरक्षा के जो जरूरी उपाय होने चाहिए, वे नहीं किए जाते। भवनों का निर्माण करते समय उनमें सुरक्षा और विशेष रूप से आग से बचाव के उपाय न करना एक अपराध ही है, लेकिन देश में ऐसे अपराध हर कहीं हो रहे हैं और उनकी रोकथाम के लिए संबंधित विभाग और सरकारें सक्रिय नहीं होतीं।

गोवा के नाइट क्लब के बारे में यह सामने आ रहा है कि वह महीनों से बिना लाइसेंस के चल रहा था और उसमें सुरक्षा के उपाय भी नहीं थे। उसका निर्माण भी नियमों के विपरीत किया गया था। जब इस नाइट क्लब का नियमों का उल्लंघन करके निर्माण हो रहा था, तब संबंधित विभाग निष्क्रिय क्यों थे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस निर्माण के बारे में उन्हें कुछ पता न चला हो। तथ्य यह है कि इस नाइट क्लब के निर्माण और संचालन में बरती जा रही लापरवाही को लेकर कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन उन पर अधिकारियों ने भी ध्यान नहीं दिया। आखिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? सब जानते हैं कि अवैध निर्माण नगर निकायों और अन्य विभागों की मिलीभगत से होते हैं। इस तरह के निर्माण में आग से बचाव के उपायों के मामले में तो रिकार्ड कुछ ज्यादा ही खराब है।

गोवा की घटना के बाद ऐसी खबरें आ रही हैं कि देश के अन्य शहरों के तमाम रेस्त्रां और बैंक्वेट हाल, होटल आदि ऐसे हैं जहां सुरक्षा और विशेषकर आग से बचाव के पर्याप्त उपाय नहीं हैं। यदि सुरक्षा उपायों का आडिट किया जाए तो शायद ही कोई निजी या सार्वजनिक इमारत निर्माण और सुरक्षा संबंधी नियम-कानूनों की कसौटी पर खरी पाई जाए। जो भी गैर-कानूनी निर्माण होते हैं, उनके प्रति नगर निकाय के अधिकारीगण आंखें मूंदे रहते हैं।

नियम विरुद्ध निर्माण में आर्किटेक्ट और ठेकेदार भी शामिल होते हैं। बहुत कम यह सुनने को मिलता है कि अवैध निर्माण में शामिल रहे किसी आर्किटेक्ट के खिलाफ कार्रवाई हुई हो और उसका लाइसेंस रद किया गया हो। लाइसेंस रद भी किया जाता है, तो कुछ महीने के लिए। ठेकेदारों के खिलाफ भी कभी कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती। समय आ गया है कि उन्हें भी अवैध निर्माण के लिए जवाबदेह बनाया जाए। आर्किटेक्ट या ठेकेदार अवैध निर्माण में भागीदार इसीलिए बनते हैं, क्योंकि उन्हें कड़ी कार्रवाई का कोई भय नहीं होता। आखिर उन्हें इसके लिए क्यों नहीं चेताया जाता कि वे अवैध और सुरक्षा उपायों की अनदेखी करने वाला निर्माण न होने दें, अन्यथा दंड के भागीदार बनेंगे।

प्रत्येक बड़ी घटना के बाद हर तरह की कार्रवाई कर यह संदेश देने की कोशिश होती है कि शासन-प्रशासन सख्त है। इससे शासन-प्रशासन की वाहवाही तो हो जाती है, लेकिन आम तौर पर यह सख्ती आगे दुर्घटनाओं को रोकने में सक्षम नहीं होती। यह कहना कठिन है कि गोवा प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, उससे जो लोग गैर-कानूनी निर्माण या सुरक्षा मानकों की अवहेलना कर रहे हैं, वे सचेत हो गए होंगे। अपने देश में हर तरह के नियम-कानून हैं, पर उनका पालन करने के लिए न तो नागरिक सचेत रहते हैं और न ही उन पर अमल सुनिश्चित कराने वाले सरकारी विभाग। शायद ही कोई अवैध निर्माण होता हो, जिसमें नगर निकाय के कर्मचारी और अधिकारी पैसे न खाते हों। नगर निकायों में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते कई बार तो लोगों को सही ढंग से निर्माण कराने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। यह भ्रष्टाचार अवैध निर्माण के साथ सुरक्षा उपायों की अनदेखी को बढ़ावा दे रहा है। यह अनदेखी अक्सर जान-माल के नुकसान का कारण बनती है। जब जान-माल का नुकसान हो जाता है, तब भी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती, जिससे उन्हें सबक मिले और अन्य अधिकारियों में डर बैठे।

यह समझा जाना चाहिए कि निर्माण और सुरक्षा उपायों पर अमल की मौजूदा व्यवस्था में जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, तब तक भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में गोवा नाइट क्लब जैसी दुर्घटनाएं रोकना संभव नहीं। हर वर्ष तमाम ऐसी घटनाएं घटती हैं, जिनमें निर्दोष नागरिक निर्माण और सुरक्षा संबंधी कमियों के कारण जान गंवाते हैं, लेकिन कोई सही सबक सीखने से इन्कार किया जा रहा है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में भूकंप के खतरों को कम करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए जिस तरह यह कहा कि क्या सबको चांद पर बसा दें, उससे भूकंप रोधी उपायों की अनदेखी होने की आशंका है। यह ठीक है कि भूकंप रोधी उपायों की चिंता करना सरकारों का काम है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वे ऐसे उपायों के पालन पर ध्यान दे रही हैं? वे तो सामान्य सुरक्षा उपायों की भी अनदेखी कर रही हैं।

अभियान

स्वप्नों में लौट आते हैं जो विदा हो चुके हैं, संस्कृति, स्मृति और आत्मा की गहराइयों से उठती एक कथा

मनुष्य का जीवन केवल जागती आंखों तक सीमित नहीं है। जैसे ही शरीर विश्राम की अवस्था में जाता है और आंखें बंद होती हैं, चेतना एक ऐसे लोक में प्रवेश करती है जहां तर्क, समय और दूरी के नियम शिथिल हो जाते हैं। इसी लोक में कई बार वे चेहरे उभर आते हैं, जिन्हें हम जीवन की यात्रा में पीछे छोड़ चुके होते हैं। मृत स्वजन स्वप्न में दिखाई देते हैं, कभी मुस्कुराते हुए, कभी मौन रहते हुए, तो कभी केवल उपस्थिति का एहसास कराते हुए। नींद खुलते ही मन भारी भी हो जाता है और कहीं न कहीं एक अजीब-सी शांति भी उतर आती है। भारतीय संस्कृति में इस अनुभव को केवल मन की कल्पना मानकर छोड़ नहीं दिया गया, बल्कि इसे जीवन, मृत्यु और चेतना के बीच चल रही एक निरंतर कथा के रूप में समझा गया है।

संस्कृति के अनुसार मृत्यु संबंधों की समाप्ति नहीं है, बल्कि देह के माध्यम से निभाया गया अध्याय पूरा होने भर है। जिनसे हमारा भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक जुड़ाव रहा हो, उनका प्रभाव हमारे भीतर संस्कार बनकर बस जाता है। वही संस्कार स्वप्न अवस्था में चित्रों और अनुभवों का रूप लेकर सामने आते हैं। दिन के उजाले में जिन भावनाओं को हम व्यस्तता, सामाजिक जिम्मेदारियों या स्वयं को संभालने के प्रयास में दबा देते हैं, वे रात की नीरवता में मुखर

हो उठती हैं। मृत स्वजनों का स्वप्न में आना इसी दबे हुए भावलोक का स्वाभाविक प्रवाह माना गया है, जहां स्मृति और आत्मा एक-दूसरे से संवाद करती हैं।

भारतीय परंपरा में यह भी माना गया है कि स्वप्न अवस्था एक ऐसा सूक्ष्म द्वार है, जहां जीवित और दिवंगत के लोक क्षणभर के लिए एक-दूसरे के निकट आ जाते हैं। इसी विश्वास ने श्राद्ध, तर्पण और पितृ पक्ष जैसी परंपराओं को जन्म दिया, ताकि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और स्मरण बना रहे। संस्कृति के पन्नों में यह वर्णन मिलता है कि जब पूर्वज स्वप्न में शांत और प्रसन्न दिखाई देते हैं, तो यह इस बात का संकेत होता है कि वे संतुष्ट हैं और अपने वंशजों पर उनकी कृपा बनी हुई है। ऐसे स्वप्नों के बाद मन में अकारण साहस, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होना भी इसी कारण माना जाता है।

वहीं कभी-कभी स्वप्न में वही स्वजन उदास, चिंतित या मौन दिखाई देते हैं। संस्कृति इसे डर या अशुभ संकेत के रूप में नहीं देखती, बल्कि इसे चेतावनी या स्मरण के रूप में समझने की सलाह देती है। यह माना जाता है कि ऐसे स्वप्न व्यक्ति को अपने जीवन, कर्म और संबंधों की ओर ध्यान देने के लिए आते हैं। कहीं न कहीं यह आत्मा की वह आवाज होती है, जो शब्दों के बिना ही बहुत कुछ कह जाती है। भारतीय दृष्टि में स्वप्न संदेश होते हैं, जिन्हें समझने के लिए धैर्य और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, न कि भय और अंधविश्वास की।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी मृत स्वजनों का स्वप्न में आना मानव मन की गहराई से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों से हमें सुरक्षा, प्रेम और मार्गदर्शन मिला होता है, उनका चेहरा संकट, तनाव या बड़े निर्णय के समय अवचेतन मन सामने ले आता है। यह मन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन भारतीय संस्कृति इसे केवल मानसिक क्रिया तक सीमित नहीं रखती। वह कहती है कि मन और आत्मा अलग-अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही प्रवाह के दो रूप हैं। इसलिए जो स्वप्न मन में उठता है, उसका प्रभाव आत्मा तक पहुंचता है और जो आत्मा में हलचल होती है, वह स्वप्न बनकर मन में उतर आती है।

कई लोगों के अनुभव बताते हैं कि किसी मृत स्वजन के स्वप्न में आने के बाद जीवन में अचानक कोई अटका हुआ कार्य पूरा हो गया, कोई पुराना डर समाप्त हो गया या मन को किसी निर्णय में स्पष्टता मिल गई। ऐसे अनुभवों ने पीढ़ियों से इस विश्वास को मजबूत किया है कि स्वप्न केवल बीते कल की छाया नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य को दिशा देने वाला संकेत भी हो सकते हैं। उपनिषदों में स्वप्न अवस्था को आत्मा की स्वतंत्र यात्रा कहा गया है, जहां वह अपने संस्कारों और स्मृतियों के साथ विचरण करती है, बिना किसी बाहरी बंधन के।

संस्कृति यह सिखाती है कि ऐसे स्वप्न आने पर व्यक्ति को अपने भीतर झांकना चाहिए। यह देखना चाहिए कि कहीं कोई अधूरा भाव, अनकहा दुःख या दबा हुआ अपराधबोध तो नहीं है। पितरों का स्मरण कर मन ही मन उनके लिए शुभकामना करना, जरूरतमंद की सहायता करना या किसी अच्छे कार्य का संकल्प लेना न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि उस अदृश्य रिश्ते को भी सम्मान प्रदान करता है, जो देह के न रहने पर भी बना रहता है।

अंत में यही कहा जा सकता है कि स्वप्न में मृत स्वजनों का दिखाई देना जीवन और मृत्यु के बीच फैली उस महीन रेखा को उजागर करता है, जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। संस्कृति के पन्ने बताते हैं कि रिश्ते समय और शरीर से बड़े होते हैं। वे स्मृति, चेतना और आत्मा के स्तर पर निरंतर बहते रहते हैं। ऐसे स्वप्न हमें डराने नहीं आते, बल्कि यह याद दिलाने आते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे भीतर और हमारे साथ वे सभी अनुभव, संस्कार और प्रेम जीवित हैं, जिन्होंने हमें वह बनाया है जो हम आज हैं।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

“संवेदनशील सरकार, सुरक्षित नागरिक”: गुजरात CMRF ने 4 वर्षों में 2,106 कैंसर मरीजों को दिया नया जीवनदान

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) संकट की घड़ी में राज्य के नागरिकों के लिए एक सशक्त सुरक्षा-कवच के रूप में उभरा है। प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं से लेकर गंभीर बीमारियों और जीवन-रक्षक उपचारों तक, इस कोष का दायरा लगातार विस्तृत होता जा रहा है। विशेष रूप से स्वास्थ्य सहायता के क्षेत्र में CMRF ने हजारों परिवारों को समय पर मदद, आर्थिक राहत और नई उम्मीद प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री राहत कोष को अधिक संवेदनशील, त्वरित और जन-केन्द्रित बनाया गया है, ताकि कोई भी जरूरतमंद आर्थिक तंगी के कारण उपचार से वंचित न रहे। उनकी प्राथमिकता “लोगों का जीवन और स्वास्थ्य सर्वोपरि” के अनुरूप यह कोष आज आम नागरिकों के लिए वास्तविक सहारा और भरोसे का माध्यम बन चुका है।

गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बन रहा CMRF

गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे मरीजों को जीवन-रक्षक चिकित्सा उपलब्ध कराना है, जिनके लिए महंगे उपचार संभव नहीं हो पाते। कैंसर, हृदय रोग, किडनी और लिवर फेल्योर, तथा ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर स्थितियाँ इस सहायता के दायरे में आती हैं। पात्रता मानदंडों के तहत आवेदक की वार्षिक आय 4 लाख रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6 लाख रुपये) से कम होनी चाहिए। इसके साथ निवासी प्रमाण-पत्र, उपचार का विस्तृत अनुमान और संबंधित मेडिकल दस्तावेज आवश्यक हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद राजस्व विभाग द्वारा विस्तृत सत्यापन किया जाता है। इसके पश्चात पूरी फाइल मुख्यमंत्री राहत कोष समिति के समक्ष भेजी जाती है, जिसमें राहत आयुक्त, अपर मुख्य सचिव (राजस्व), मुख्य सचिव और स्वयं मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। समिति की मंजूरी के बाद स्वीकृत राशि सीधे अस्पताल या रोगी के खाते में स्थानांतरित की जाती है, जिससे मरीज को समय पर उपचार में कोई बाधा न आए।

- बोन मैरो ट्रांसप्लांट सहित ब्लड कैंसर के 450 मामलों और अन्य 1,656 कैंसर मरीजों का सहारा बना CMRF
- 2021-2025 के दौरान 2,106 कैंसर रोगियों को उपचार के लिए मिली 31.55 करोड़ से अधिक की मदद
- लिवर, किडनी, हृदय और फेफड़ों के प्रत्यारोपण जैसे महंगे और जटिल उपचारों में भी मिलती है CMRF से वित्तीय मदद

CMRF से 4 वर्षों में 2,106 कैंसर मरीजों को उपचार के लिए मिली 31.55 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता

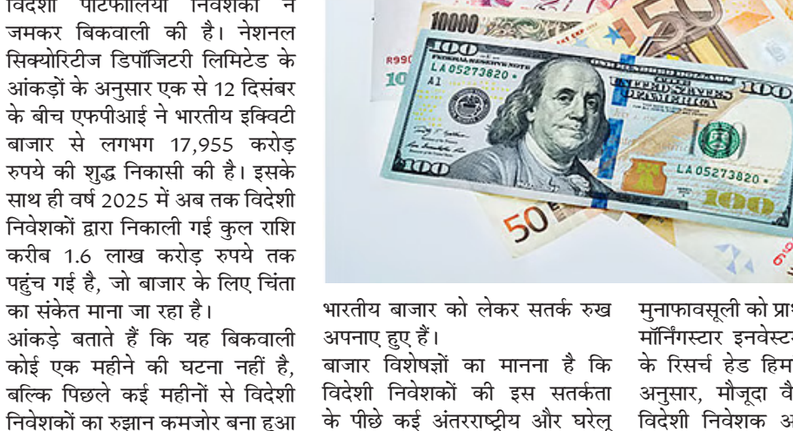

2021 से 2025 के बीच मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) ने गुजरात में कैंसर से जूझ रहे 2,106 मरीजों को महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान की है जिससे उन्हें नया जीवनदान मिला है। इस अवधि में 2,106 कैंसर मरीजों के उपचार के लिए CMRF की ओर से 31.55 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए रोग-वार आंकड़ों के अनुसार, ब्लड कैंसर (जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट के मामले भी शामिल हैं) के 450 मरीजों को राहत मिली, जबकि अन्य प्रकार के कैंसर से पीड़ित 1,656 मरीजों को CMRF से आर्थिक सहायता मिली है। कैंसर सहायता के अलावा CMRF के तहत लिवर, किडनी, हृदय और फेफड़ों के प्रत्यारोपण जैसे महंगे और जटिल उपचारों में भी महत्वपूर्ण आर्थिक मदद दी जा रही है।

गुजरात के शीर्ष कैंसर अस्पतालों में उपलब्ध है CMRF से सीधी आर्थिक मदद

अहमदाबाद स्थित गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (GCRI), राजकोट के नथालाल पारिख कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट और बी.टी. सावानी हॉस्पिटल, सूरत के भारत कैंसर हॉस्पिटल, किरण मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल तथा AAIHMS जैसे प्रमुख चिकित्सा संस्थान मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) के तहत सहायता व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इन सभी अस्पतालों में कैंसर से संबंधित आधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हैं और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में समय पर उपचार भी सुनिश्चित जाता है।

केरल की राजनीति में नया अध्याय, तिरुवनंतपुरम जीत के बाद भाजपा के विस्तार का भरोसा: मोहन यादव

(जीएनएस)। इंदौर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ऐतिहासिक जीत को दक्षिण भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव बताते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में भाजपा केरल में लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। रविवार को इंदौर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव का परिणाम केवल एक स्थानीय जीत नहीं है, बल्कि यह उस बदलाव का संकेत है, जो केरल की राजनीति में धीरे-धीरे आकार ले रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है और इसका प्रभाव अब देश के हर कोने में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की विजय पताका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक लहरा रही है और जहां-जहां पार्टी को जनता का समर्थन मिला है, वहां सुशासन, विकास और पारदर्शिता के नए मानक स्थापित हुए हैं। यादव ने यह भी कहा कि केरल जैसे राज्य में, जहां दशकों से वामपंथी दलों का प्रभुत्व रहा है, वहां भाजपा नीत राजग की यह जीत जनता की बदलती सोच और विकास के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव के नतीजों पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इससे 45 वर्षों से चले आ रहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नीत वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के शासन का अंत हुआ है। उन्होंने इसे केरल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत बताया और कहा कि जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह केवल परंपरा के नाम पर सत्ता नहीं चाहती, बल्कि विकास, जवाबदेही और सुशासन को प्राथमिकता दे रही है।

मोहन यादव ने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में भाजपा केरल में अपनी संगठनात्मक मजबूती बढ़ाएगी और जनता के मुद्दों के साथ लगातार आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे के विकास और सुशासन की नीति का प्रभाव अब केरल की जनता तक भी पहुंच रहा है। यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में पहले भाजपा को सीमित समर्थन मिलता था, वहां भी अब पार्टी को व्यापक जनसमर्थन मिलने लगा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की राजनीति सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सेवा, विकास और विश्वास के लिए है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में मिली जीत इसी सोच की जीत है। उन्होंने भरोसा जताया कि केरल की जनता आने वाले समय में भाजपा को और अधिक अवसर देगी और राज्य की राजनीति में संतुलन और विकास की नई धारा स्थापित होगी।

विदेशी पूंजी की लगातार विदाई से बाजार पर दबाव दिसंबर में करीब 18 हजार करोड़ की निकासी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बेचैनी लगातार बनी हुई है और दिसंबर के पहले पखवाड़े में भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जमकर बिकवाली की है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के आंकड़ों के अनुसार एक से 12 दिसंबर के बीच एफपीआई ने भारतीय इक्विटी बाजार से लगभग 17,955 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की है। इसके साथ ही वर्ष 2025 में अब तक विदेशी निवेशकों द्वारा निकाली गई कुल राशि करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो बाजार के लिए चिंता का संकेत माना जा रहा है।

आंकड़े बताते हैं कि यह बिकवाली कोई एक महीने की घटना नहीं है, बल्कि पिछले कई महीनों से विदेशी निवेशकों का रुझान कमजोर बना हुआ है। नवंबर महीने में भी एफपीआई ने करीब 3,765 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की थी। हालांकि अक्टूबर में विदेशी निवेशकों ने कुछ राहत देते हुए 14,610 करोड़ रुपये का निवेश किया था, लेकिन जुलाई से सितंबर के बीच लगातार बिकवाली के चलते बाजार पर दबाव बना रहा। दिसंबर में फिर से तेज निकासी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विदेशी निवेशक फिलहाल

भारतीय बाजार को लेकर सतर्क रुख अपनाए हुए हैं।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी निवेशकों की इस सतर्कता के पीछे कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारण एक साथ काम कर रहे हैं। रुपये में लगातार कमजोरी, अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ऊंची ब्याज दरें, वैश्विक स्तर पर सख्त मौद्रिक नीति और तरलता की कमी ने उभरते बाजारों से पूंजी निकालने की प्रवृत्ति को बढ़ाया है। इसके अलावा भारतीय शेयरों का मूल्यांकन भी कई विदेशी निवेशकों को महंगा नजर आ रहा है, जिससे वे नए निवेश के बजाय मुनाफावसूली को प्राथमिकता दे रहे हैं।

मॉर्निंगस्टार इनवेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के रिसर्च हेड हिमांशु श्रीवास्तव के अनुसार, मौजूदा वैश्विक हालात में विदेशी निवेशक अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्थिर रिटर्न वाले विकसित बाजारों की ओर झुक रहे हैं। वहीं एंजेल वन के सीनियर एनालिस्ट वकारजावेद खान का कहना है कि साल के अंत में पोर्टफोलियो का पुनर्संतुलन, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और रुपये की गिरावट ने भी एफपीआई की बिकवाली को और तेज किया है। इन सभी कारणों का संयुक्त असर भारतीय बाजार से विदेशी पूंजी के बाहर जाने के रूप में दिखाई दे रहा है।

इसके बावजूद भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली है, जिसका श्रेय घरेलू निवेशकों को जाता है। दिसंबर के पहले दो हफ्तों में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने लगभग 39,965 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिससे विदेशी निवेशकों की बिकवाली का असर काफी हद तक संतुलित हो गया। म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और अन्य घरेलू संस्थानों की मजबूत भागीदारी ने बाजार को सहारा दिया है और निवेशकों के भरोसे को बनाए रखा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में यदि वैश्विक हालात में कुछ स्थिरता आती है और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता कम होती है, तो विदेशी निवेशकों की बिकवाली की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। इक्विटी के अलावा डेट बाजार में भी एफपीआई की गतिविधियां मिश्रित रहीं, जहां सामान्य सीमा के तहत 310 करोड़ रुपये की निकासी देखी गई, जबकि वॉलंटरी रिटेंशन रूट के माध्यम से 151 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। कुल मिलाकर विदेशी पूंजी का रुख फिलहाल सतर्क बना हुआ है, लेकिन घरेलू निवेशकों की मजबूती ने बाजार को संतुलन में बनाए रखा है।

डिजिटल बैंकिंग की नई उड़ान: YONO के जरिए 20 करोड़ ग्राहकों तक पहुंचने की तैयारी में SBI

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में एक नई और निर्णायक छलांग लगाने की तैयारी में है। बैंक ने अपने प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म योनो (YONO) को लेकर महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करते हुए अगले दो वर्षों में इसके यूजर बेस को दोगुना कर 20 करोड़ तक पहुंचाने की योजना बनाई है। एसबीआई के चेयरमैन सी. एस. शेट्टी ने स्पष्ट किया है कि बैंक का भविष्य डिजिटल विस्तार से जुड़ा है और योनो 2.0 इस रणनीति की रीढ़ साबित होगा। वर्तमान में योनो से करीब 10 करोड़ ग्राहक जुड़े हुए हैं, जिन्हें बढ़ाकर 20 करोड़ करने के लिए बैंक तकनीकी ढांचे, ग्राहक अनुभव और डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर बड़े स्तर पर निवेश कर रहा है।

चेयरमैन शेट्टी के अनुसार, योनो 2.0 के तहत इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के लिए एक साझा कोड सिस्टम अपनाया गया है, जिससे सभी डिजिटल चैनलों पर ग्राहकों को एक समान, सुरक्षित और सहज अनुभव मिल सके। इस एकीकृत व्यवस्था से खाता खोलने, लेन-देन, लोन, निवेश और अन्य बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच पहले से कहीं अधिक तेज और सरल होगी। उन्होंने कहा कि योनो केवल एक ऐप नहीं, बल्कि एसबीआई की डिजिटल सोच का केंद्र है, जिसके जरिए बैंक नए उत्पादों और सेवाओं को तेजी से बाजार में उतार सकेगा और बदलती ग्राहक अपेक्षाओं के अनुरूप खुद को ढाल पाएगा। एसबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि डिजिटल विस्तार के बावजूद बैंक की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है। फिलहाल बैंक को इक्विटी कैपिटल जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं है और अगले पांच से छह वर्षों तक लगभग 15 प्रतिशत का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बनाए रखने की स्थिति में है। चालू वित्त वर्ष में बैंक को करीब 14 प्रतिशत की क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीद है, जो देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी और बैंकिंग सेक्टर में भरोसे को दर्शाती है।

ऋण वृद्धि के मोर्चे पर एसबीआई का फोकस रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई यानी RAM सेक्टर पर बना हुआ है। यह सेक्टर बैंक के कुल ऋण पोर्टफोलियो का लगभग 67 प्रतिशत हिस्सा है और सितंबर तक इसका आकार 25 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर चुका है। इसके साथ ही गोल्ड लोन में मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जबकि एक्सप्रेस क्रेडिट जैसे अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन में भी दो अंकों की वृद्धि की संभावना जताई गई है। बैंक का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार से इन सभी क्षेत्रों में ऋण वितरण और ग्राहक पहुंच और अधिक प्रभावी होगी।

एसबीआई प्रबंधन का कहना है कि योनो के माध्यम से बैंक न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी डिजिटल बैंकिंग की पहुंच बढ़ाना चाहता है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना, लेन-देन को सुरक्षित बनाना और ग्राहकों को एक ही मंच पर सभी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। योनो के जरिए एसबीआई डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को मजबूत आधार देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में यह प्लेटफॉर्म देश की बैंकिंग प्रणाली में एक नया मानक स्थापित कर सकता है।

डांस की मस्ती में मौत को दावत, बंदूक लहराकर युवक ने की फायरिंग, VIDEO वायरल होते ही पुलिस की त्वरित कार्रवाई

(जीएनएस)। राजस्थान के डीग जिले से सामने आया एक वीडियो एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जश्न और कानून को चुनौती देने की यह प्रवृत्ति कब थमेगी। नगर थाना क्षेत्र के कसाई मोहल्ले का बताया जा रहा यह वीडियो महज 13 सेकेंड का है, लेकिन इसमें दिखी लापरवाही और बेखौफ रवैया बेहद खतरनाक है। वीडियो में एक लंबे बालों वाला युवक, जिसका नाम जीशान बताया जा रहा है, हाथ में बंदूक लेकर सड़क पर खुलेआम नाचता नजर आता है। डांस के दौरान वह कभी बंदूक को हवा में लहराता है, तो कभी लोगों के बीच घुमाता है और फिर अचानक फायर कर देता है। यह पूरा दृश्य किसी शादी या निजी आयोजन का बताया जा रहा है, जहां आसपास मौजूद लोगों की सुरक्षा की परवाह किए बिना युवक ने यह दुस्साहस किया।

वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में भी हलचल मच गई। नगर थाने के एसएचओ लाखन सिंह ने देर रात ही कार्रवाई करते हुए दो युवकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मौके से हथियार को भी जब्त कर लिया है और दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह वीडियो कब का है और जिस बंदूक से फायर किया गया वह लाइसेंसी है या अवैध। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब देश के अलग-अलग हिस्सों से हर्ष फायरिंग की वजह से मौत और गंभीर चोटों की खबरें लगातार आ रही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में भाजपा नेता धर्मेंद्र भाटी की गोली लगने से मौत हो गई थी। चोला थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में अजयनगर से आई एक बारात के दौरान चली गोली ने पूरे समारोह को मातम में बदल दिया। इसी तरह 25 नवंबर को मेरठ में भी एक शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में छत से बारात देख रही एक किशोरी की जान चली गई थी। गली में निकली बारात के बीच चली गोली सीधे किशोरी को जा लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

इन घटनाओं के बावजूद हर्ष फायरिंग की प्रवृत्ति थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस लगातार चेतावनी देती है, अभियान चलाती है और कार्रवाई भी करती है, लेकिन जश्न के नाम पर कानून को ताक पर रखने वाले लोग दूसरों की जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आते। डीग का यह मामला भी उसी लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना सोच का उदाहरण है, जहां कुछ सेकेंड के दिखावे और शौक के लिए किसी की जिंदगी खतरे में डाल दी गई। अब देखना यह होगा कि पुलिस की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या इस तरह की घटनाओं पर सख्ती से लगाम लग पाती है या नहीं।

एसआईआर को लेकर बयानबाजी पर मौलाना बरेलवी का कड़ा ऐतराज, अखिलेश यादव से संयम बरतने की अपील

(जीएनएस)। बरेली। चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को पारदर्शी, सटीक और त्रुटिरहित बनाना है, न कि किसी विशेष समुदाय, खासकर मुसलमानों को निशाना बनाना। ऐसे में इस संवेदनशील मुद्दे पर भ्रामक और गैर-जिम्मेदार बयान देना न केवल गलत है, बल्कि समाज में अनावश्यक भ्रम और तनाव भी पैदा करता है।

मौलाना बरेलवी ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मृत मतदाताओं के नाम, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोगों की प्रविष्टियां और मतदाता सूची में दर्ज तकनीकी त्रुटियों को ठीक किया जाता है। यह एक नियमित और संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनाया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुसलमानों के वोट काटे जाने का आरोप पूरी तरह निराधार और गुमराह करने वाला है। इस तरह के बयान चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं, जो उचित नहीं है।

मौलाना रजवी ने कहा कि देश के जिम्मेदार नेताओं को चाहिए कि वे हर मुद्दे को सांप्रदायिक नजरिये से देखने से बचें। लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता सभी नागरिकों के हित में होती है, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय से संबंधित हों। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि देशभर में मुसलमानों ने एसआईआर प्रक्रिया में सक्रिय, सकारात्मक और जिम्मेदार भूमिका निभाई है। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने दस्तावेज उपलब्ध कराए, फॉर्म भरे और चुनाव आयोग के अधिकारियों को सहयोग दिया, ताकि मतदाता सूची अधिक सटीक और भरोसेमंद बन सके। उन्होंने कहा कि इस तरह की भागीदारी यह साबित करती है कि मुसलमान लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास रखते हैं और देश की संस्थाओं को मजबूत करने में अपना योगदान देते हैं। मौलाना बरेलवी ने अखिलेश यादव सहित सभी राजनीतिक नेताओं से अपील की कि वे तथ्यों के आधार पर बयान दें, अफवाहों से बचें और जनता को भ्रमित करने वाले आरोप लगाने के बजाय लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि चुनावी प्रक्रियाओं को संदेह और राजनीति से ऊपर रखा जाए, ताकि आम नागरिक का भरोसा बना रहे।

घने कोहरे की चादर में लिपटा नोएडा, सड़कों पर थमी रफ्तार और बढ़ी चिंता

(जीएनएस)। नोएडा। औद्योगिक नगरी नोएडा रविवार सुबह घने कोहरे की गिरफ्त में नजर आई, जहां तड़के से ही आसमान से लेकर सड़कों तक सफेद धुंध की मोटी परत छा गई। हालात ऐसे रहे कि सुबह करीब दस बजे तक शहर के अधिकांश हिस्सों में दृश्यता बेहद कम बनी रही और वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए सफर करना पड़ा। खुले और मैदानी इलाकों में दृश्यता घटकर 15 मीटर से भी कम रह गई, जिससे एक्सप्रेसवे और हाईवे पर चलना जोखिम भरा हो गया।

कोहरे के साथ-साथ वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति ने भी हालात को और बिगाड़ दिया। नोएडा एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग-91 और एनएच-24 समेत प्रमुख मार्गों पर वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर सामने से आ रहे वाहनों का पता बेहद नजदीक आने पर चला, जिससे अचानक ब्रेक लगाने और टकराव की स्थिति बनती रही। ट्रैफिक की रफ्तार काफी धीमी रही और कुछ स्थानों पर जाम जैसे हालात भी देखने को मिले।

मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता का स्तर 61 प्रतिशत रहने के कारण ठंड के साथ कोहरा और अधिक घना हो गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि कम तापमान, नमी और प्रदूषण के मेल ने कोहरे को लंबे समय तक टिकाए रखा, जिससे सुबह के समय हालात सामान्य होने में देरी हुई।

घने कोहरे और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। सोमवार से प्रमुख एक्सप्रेसवे और सड़कों पर वाहनों की गति सीमा घटाने का फैसला लागू कर दिया गया है। 15 दिसंबर की रात 12 बजे से यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है, जबकि भारी वाहनों के लिए यह सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। यह व्यवस्था 15 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। इसी तरह नोएडा एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति 75 किमी प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 50 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। एलिवेटेड रोड पर भी हल्के वाहनों के लिए 50 और भारी वाहनों के लिए 40 किमी प्रति घंटे की सीमा लागू की गई है। यातायात पुलिस ने सड़कों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए जगह-जगह सूचना बोर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं। पुलिस उपायुक्त (यातायात) डॉ. प्रवीन रंजन सिंह के अनुसार एनसीआर में ग्रैप-4 लागू होने के कारण दिल्ली में प्रवेश करने वाले बीएस-3 और बीएस-4 डीजल वाहनों समेत कुछ श्रेणी के भारी मालवाहक वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। इसके तहत चिल्ला, डीएनडी, कालिंदी कुंज और अशोक नगर जैसे प्रमुख बॉर्डर प्वाइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है और प्रतिबंधित वाहनों को वहीं से वापस लौटाया जा रहा है। दूर-दराज के राज्यों से दिल्ली की ओर जा रहे कई वाहन चालकों को इस कारण असुविधा का सामना करना पड़ा, हालांकि पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें नियमों की जानकारी देकर समझाया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोहरे के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके।

अंबाजी में वन भूमि विवाद ने लिया हिंसक रूप, पुलिस और वन विभाग पर सुनियोजित हमला, इंस्पेक्टर तीर लगने से गंभीर घायल

(जीएनएस)। बनासकांठा जिले के प्रसिद्ध तीर्थस्थल अंबाजी के पास जंगल की जमीन को लेकर उठा विवाद रविवार को अचानक हिंसा में तब्दील हो गया। गब्बर रोड से सटे पडलिया गांव में फॉरेस्ट की भूमि पर चल रहे वृक्षारोपण कार्य का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जो देखते ही देखते उग्र प्रदर्शन और फिर बड़े हमले में बदल गया। हालात इतने बिगड़ गए कि वन विभाग के कर्मचारी और मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी जान बचाकर इधर-उधर भागने को मजबूर हो गए। ग्रामीणों की ओर से की गई जबरदस्त पत्थरबाजी, तीरों से हमला और आगजनी ने पूरे इलाके को कुछ देर के लिए रणक्षेत्र में बदल दिया।

घटना की शुरुआत उस समय हुई जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम पडलिया गांव के पास वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप था कि यह जमीन उनके उपयोग की है, जबकि वन विभाग इसे आरक्षित वन क्षेत्र बता रहा था। इसी विवाद के चलते पहले बहस हुई और फिर देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। कुछ ही देर में हालात हाथ से निकल गए और भीड़ ने वन विभाग के अधिकारियों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अचानक हुए हमले से मौके पर भगदड़ मच गई और कई कर्मचारी घायल हो गए।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन अधिकारियों ने तुरंत अंबाजी पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही अंबाजी पुलिस इंस्पेक्टर आर.बी. गोहिल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। लेकिन जैसे ही पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की, हमलावर भीड़ ने पुलिस को भी निशाना बना लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अचानक तीर-धनुष और पत्थरों से हमला किया गया। इसी दौरान एक तीर पुलिस इंस्पेक्टर आर.बी. गोहिल के कान में जा लगा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हिंसा यहीं नहीं रुकी। बताया जा रहा है कि करीब एक हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ ने वन विभाग और पुलिस पर संगठित तरीके से हमला किया। कई पुलिसकर्मी और वनकर्मी घायल हुए। कुछ सरकारी वाहनों में आग लगा दी गई, वहीं कई वाहनों के टायर काट दिए गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए करीब 50 राउंड फायरिंग करनी पड़ी और लगभग 20 आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके बाद कहीं जाकर भीड़ को पीछे हटाया जा सका। घायलों को अंबाजी सिविल अस्पताल, पालनपुर सिविल अस्पताल और कुछ निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल नौ पुलिसकर्मियों को पालनपुर रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पालनपुर विधायक अनिकेत ठाकर अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत कर बेहतर इलाज के निर्देश दिए।

घटना के बाद जिले में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई। बनासकांठा के जिला कलेक्टर मिहिर पटेल स्वयं अंबाजी पहुंचे और सिविल अस्पताल में भर्ती घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि यह हमला सामान्य विरोध नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित प्रतीत होता है। पत्थरों के साथ-साथ तीरों का इस्तेमाल और एक साथ बड़ी संख्या में लोगों का हमला इस बात की ओर इशारा करता है कि पूरी घटना की पहले से तैयारी की गई थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद अंबाजी और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है, ताकि किसी तरह की दोबारा हिंसा न हो। इस हिंसक घटना ने एक बार फिर वन भूमि विवाद, प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच संवाद की कमी और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों को उजागर कर दिया है।

इकनौर के जंगल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, मुठभेड़ में दो बदमाश घायल

(जीएनएस)। इटावा। जनपद इटावा के थाना बकेवर क्षेत्र में स्थित इकनौर के घने जंगल उस वक्त गोलियों की आवाज से गूंज उठे, जब बकेवर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने वहां चल रही अवैध असलहा फैक्ट्री पर अचानक दबिश दी। लंबे समय से गुप्त रूप से संचालित इस फैक्ट्री में बदमाश देसी तमंचे और कारतूस तैयार कर आसपास के जिलों में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस की कार्रवाई के दौरान बदमाशों ने टीम पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दो शातिर अपराधी गोली लगने से घायल होकर मौके पर ही दबोच लिए गए, जबकि उनका एक साथी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि इकनौर के जंगल में अवैध हथियारों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और इन्हें इटावा, औरैया समेत कई जिलों में सप्लाई किया जाता है। सूचना की पुष्टि के बाद क्राइम ब्रांच और बकेवर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने पूरी रणनीति के साथ जंगल की घेराबंदी की। जैसे ही पुलिस टीम संदिग्ध स्थान पर पहुंची, वहां मौजूद बदमाशों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मुठभेड़ की स्थिति बन गई।

पुलिस ने आत्मरक्षा में संयमित जवाबी फायरिंग की, जिसमें दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल के रास्ते फरार हो गया। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी।

छापेमारी के दौरान जंगल से 24 से अधिक निर्मित और अर्धनिर्मित अवैध हथियार, भारी मात्रा में कारतूस, मोबाइल फोन, हथियार बनाने के उपकरण और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सराय चोरी निवासी सज्जन और निवाड़ी निवासी अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे लंबे समय से जंगल में छिपकर अवैध असलहा तैयार कर रहे थे और इसे अलग-अलग जिलों में सप्लाई कर मोटा मुनाफा कमा रहे थे। दोनों के खिलाफ पहले भी अवैध हथियार तस्करी और आपराधिक मामलों के रिकॉर्ड मौजूद हैं और वे जेल भी जा चुके हैं।

घायल आरोपियों को प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया, जहां से स्वस्थ होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने अलग-अलग टीमें गठित कर दी हैं और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

रामलीला मैदान से सत्ता को सीधी चुनौती, 'वोट चोरी' के सवाल पर कांग्रेस का बड़ा राजनीतिक आह्वान

(जीएनएस)। दिल्ली। राजधानी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित 'वोट चोरी' रैली के जरिए कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और चुनाव आयोग पर सीधा और तीखा हमला बोला। हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी में कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई करार दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंच से कहा कि आज देश में असली संघर्ष सत्य और सत्ता के बीच चल रहा है और कांग्रेस इस संघर्ष में सत्य के साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के संरक्षण में चुनावी व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को एक-एक कर झुकाया जा रहा है।

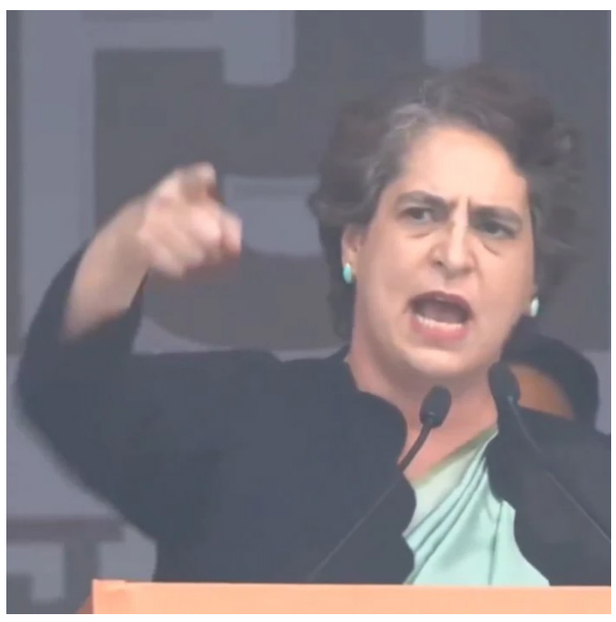

राहुल गांधी ने अपने भाषण में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कथित बयान का हवाला देते हुए कहा कि संघ की विचारधारा सत्य की नहीं बल्कि सत्ता की है। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा सत्य में बसती है, 'सत्यम शिवम सुंदरम' हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है और यही देश की ताकत है। राहुल गांधी ने कहा कि जनता सब देख रही है और वह दिन दूर नहीं जब सत्य के साथ खड़े होकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की सत्ता को लोकतांत्रिक तरीके से हटाया जाएगा। उन्होंने भरोसे के साथ कहा कि यह लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन जीत अंततः जनता और सत्य की ही होगी।

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कानून बदलकर उन्हें जवाबदेही से बाहर कर दिया गया है, जिससे निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा को गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर इस कानून को बदलेगी और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को फिर से स्थापित करेगी। गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता के रहते बहादुरी दिखाना आसान है, लेकिन सत्ता जाते ही वही बहादुरी गायब हो जाती है। उनके इस बयान पर मैदान में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की।

रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संसद में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जैसे भावनात्मक मुद्दों पर बहस तो होती है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य जैसे सवालों पर चर्चा करने से सरकार कतराती है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव कराने का साहस है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, तब सच्चाई सामने आ जाएगी।

उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूरा विपक्ष एक स्वर में कह रहा है कि उसे चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रहा।

प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश की लगभग हर संवैधानिक संस्था को अपने दबाव में ला दिया है। चुनाव प्रक्रिया के हर चरण पर संदेह पैदा हो गया है, जिससे लोकतंत्र की नींव कमजोर हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस हालात को स्वीकार नहीं करेगी और सड़क से संसद तक लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ेगी।

रामलीला मैदान की यह रैली सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों से पहले कांग्रेस की बड़ी रणनीतिक घोषणा के तौर पर देखी जा रही है। 'वोट चोरी' के मुद्दे को केंद्र में रखकर कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिया है कि वह सरकार और संस्थाओं की कार्यप्रणाली को लेकर आक्रामक रुख अपनाएगी। रैली के जरिए कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के साथ-साथ यह संदेश भी देने की कोशिश की कि आने वाला राजनीतिक संघर्ष सत्ता से ज्यादा लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई होगा।

बीजेपी की नई पीढ़ी को बड़ी जिम्मेदारी, नितिन नबीन बने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक ढांचे में एक अहम और दूरगामी राजनीतिक फैसला लेते हुए नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को बीजेपी की भविष्य की रणनीति, युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने और संगठन को नई ऊर्जा देने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। महज 45 वर्ष की उम्र में नितिन नबीन को यह जिम्मेदारी सौंपकर पार्टी ने साफ कर दिया है कि आने वाले वर्षों में वह अनुभव और युवा जोश के संतुलन के साथ आगे बढ़ना चाहती है। नितिन नबीन का राजनीतिक सफर जमीनी स्तर से शुरू हुआ है। छात्र राजनीति से लेकर संगठन के विभिन्न दायित्वों तक उन्होंने पार्टी के लिए लगातार काम किया है। उनका नाम उन नेताओं में लिया जाता है जो कैमरे की चकाचौंध से दूर रहकर संगठनात्मक मजबूती पर फोकस करते रहे हैं। यही कारण है कि पार्टी नेतृत्व उन्हें एक लो-प्रोफाइल, अनुशासित और विवादमुक्त नेता के रूप में देखता है, जो संगठन को अंदर से मजबूत करने की क्षमता रखते हैं। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि नबीन की नियुक्ति कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश है कि पार्टी में कड़ी मेहनत, निष्ठा और संगठन के प्रति समर्पण के दम पर शीर्ष पदों तक पहुंचा जा सकता है। नबीन की कार्यशैली को युवाओं से जुड़ने वाली, आक्रामक लेकिन संतुलित रणनीति के तौर पर देखा जाता है। पार्टी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में युवा वर्ग को बीजेपी से जोड़ने की मुहिम और तेज होगी।

सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी नितिन नबीन की नियुक्ति को अहम माना जा रहा है। उनका कायस्थ समुदाय से होना शहरी क्षेत्रों और खासतौर पर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बीजेपी के लिए राजनीतिक संतुलन और सामाजिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि नबीन की इन क्षेत्रों में पकड़ और समझ आने वाले चुनावों में उपयोगी साबित हो सकती है।

नितिन नबीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़े रहे हैं और उनके राजनीतिक संस्कार बचपन से ही संघ और बीजेपी के माहौल में विकसित हुए हैं। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा भी पार्टी से जुड़े रहे, जिससे संगठन और विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और गहरी मानी जाती है। एबीवीपी और युवा मोर्चा में काम करने का अनुभव उन्हें संगठन की नब्ज समझने वाला नेता बनाता है।

इस नियुक्ति के साथ बीजेपी ने साफ संकेत दिया है कि पार्टी केवल वर्तमान राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों के लिए नेतृत्व तैयार कर रही है। युवा नेतृत्व, संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति—इन तीनों मोर्चों पर नितिन नबीन की भूमिका अहम मानी जा रही है। पार्टी के भीतर यह संदेश भी गया है कि बीजेपी अब भविष्य की राजनीति के लिए नई पीढ़ी को आगे लाने में पूरी तरह गंभीर है।

मां के एक वाक्य ने तोड़ा धैर्य, 11वीं मंजिल पर थमी सांसें; दमकलकर्मियों की सूझबूझ से बची नाबालिग की जान

(जीएनएस)। सूरत। गुजरात के सूरत शहर के अलथान इलाके में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। महज 17 साल की एक नाबालिग लड़की उस वक्त मौत और जिंदगी के बीच झूलती नजर आई, जब वह एक बहुमंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर छत की दीवार पर खड़ी होकर कूदने की धमकी देने लगी। यह पूरा घटनाक्रम उस एक वाक्य से शुरू हुआ, जो गुस्से में उसकी मां के मुंह से निकल गया था—"मर जा।" यही शब्द लड़की के दिल को इस कदर चुभ गया कि वह खुद को खत्म करने का फैसला कर बैठी।

सुबह के समय जब लोग रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, तभी अचानक इमारत की छत से आती चीख-पुकार ने सबका ध्यान खींचा। ऊपर देखा तो एक नाबालिग लड़की दीवार पर खड़ी थी और जोर-जोर से कह रही थी कि वह कूद जाएगी। यह दृश्य देखकर नीचे मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। देखते ही देखते इमारत के नीचे भारी भीड़ जमा हो गई। हर किसी के चेहरे पर डर और चिंता साफ नजर आ रही थी। किसी ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, तो किसी ने पुलिस को फोन किया।

इस बीच लड़की के परिवार के सदस्य भी छत पर पहुंचे और उसे नीचे आने के लिए मनाने लगे। कभी प्यार से, कभी हाथ जोड़कर, कभी रोते हुए उसे समझाने की कोशिश की गई, लेकिन गुस्से और भावनात्मक उथल-पुथल में घिरी लड़की किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह बार-बार यही कह रही थी कि उसे अब जीना नहीं है। मां की कही बात उसके मन में इस कदर घर कर गई थी कि उसे हर तरफ से खुद को अकेला और अपमानित महसूस हो रहा था।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम हाइड्रोलिक क्रेन और सेफ्टी नेट के साथ मौके पर पहुंची। हालात की गंभीरता को देखते हुए दमकल कर्मियों ने तुरंत रणनीति बनाई। एक टीम इमारत के नीचे मजबूत सेफ्टी नेट के साथ तैनात हो गई, ताकि अगर लड़की छलांग लगाती है तो उसे बचाया जा सके। दूसरी टीम क्रेन के जरिए छत की ओर बढ़ने लगी। नीचे खड़े लोग सांस रोककर यह पूरा दृश्य देख रहे थे। हर सेकंड भारी लग रहा था।

जब हाइड्रोलिक क्रेन ऊपर की ओर बढ़ी, तो लड़की और ज्यादा उत्तेजित हो गई और कूदने की तैयारी करने लगी। स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी थी। ऐसे में दमकल कर्मियों ने धैर्य और समझदारी का परिचय दिया। उन्होंने लड़की से बात करते हुए उसका ध्यान भटकाए रखा। उससे उसके भविष्य, सपनों और परिवार की बात की गई। इसी दौरान जैसे ही उसका ध्यान कुछ पल के लिए इधर-उधर हुआ, पीछे से एक दमकल कर्मी ने तेजी और सतर्कता के साथ उसे पकड़ लिया और सुरक्षित स्थान पर खींच लिया।

जैसे ही लड़की को सुरक्षित नीचे लाया गया, वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। कई महिलाओं की आंखों में आंसू थे, तो कई लोग दमकल कर्मियों की बहादुरी और सूझबूझ की सराहना करते नजर आए। लड़की को प्राथमिक उपचार और काउंसलिंग के लिए भेजा गया, ताकि उसे मानसिक रूप से संभाला जा सके।

यह घटना सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक चेतावनी भी है। गुस्से में कहे गए शब्द कभी-कभी सामने वाले के मन पर गहरा घाव छोड़ जाते हैं। एक पल की लापरवाही किसी की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। सूरत की यह घटना बताती है कि बच्चों और किशोरों की भावनाओं को समझना, उनसे संवाद बनाए रखना और शब्दों का चयन सोच-समझकर करना कितना जरूरी है। समय रहते सूझबूझ और मानवीय संवेदनशीलता ने एक मासूम जिंदगी को बचा लिया, लेकिन यह सवाल भी छोड़ गई कि क्या हम अपने शब्दों की ताकत को सच में समझते हैं?

अस्थि विसर्जन की यात्रा मातम में बदली, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर काल बनकर टूटी तेज रफ्तार बस

(जीएनएस)। हमीरपुर। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशहाल परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। अस्थि विसर्जन के लिए प्रयागराज जा रहे एक ही परिवार के वाहन को तेज रफ्तार टूरिस्ट बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दो सगे भाइयों समेत चार लोगों की मौके और इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा मौदहा क्षेत्र के इचौली गांव के पास उस समय हुआ, जब बोलेरो वाहन एक्सप्रेस-वे पर आगे बढ़ रहा था और पीछे से आई बस ने उसे जबरदस्त रफ्तार में कुचल दिया।

जानकारी के अनुसार महोबा जिले के खन्ना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्योड़ी गांव निवासी एक परिवार अपनी बुजुर्ग महिला परिजन के निधन के बाद अस्थि विसर्जन के लिए प्रयागराज जा रहा था। धार्मिक अनुष्ठान और श्रद्धा के भाव के साथ निकले इस परिवार को क्या पता था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और वाहन में सवार लोग बुरी तरह फंस गए।

दुर्घटना में बोलेरो सवार सिद्धगोपाल (65), रामसहोदर (40) और घनश्याम (55) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल सोनू (35), राधेश्याम और आशाराम को तत्काल एंबुलेंस से बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान सोनू ने भी दम तोड़ दिया। मृतकों में रामसहोदर और घनश्याम सगे भाई थे, जिनकी एक साथ मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

जहरीली हवा की गिरफ्त में एनसीआर, धुंध ने बनाया पूरा इलाका गैस चैंबर

(जीएनएस)। नोएडा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक बार फिर वायु प्रदूषण के भीषण संकट में फंस गया है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि सुबह होते ही आसमान में सूरज की जगह जहरीली धुंध की मोटी परत दिखाई दे रही है। सड़कों, इमारतों और पेड़ों पर छाई धूसर चादर ने पूरे एनसीआर को गैस चैंबर में तब्दील कर दिया है। सांस लेना तक मुश्किल हो गया है और आंखों में जलन, गले में खराश और सीने में भारीपन जैसी शिकायतें आम हो चली हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के चौथे चरण को लागू कर दिया है, जो प्रदूषण के आपात स्तर को दर्शाता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों के अनुसार नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर बनकर उभरा है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 469 तक पहुंच गया। दिल्ली में यह 460, गाजियाबाद में 459 और ग्रेटर नोएडा में 442 दर्ज किया गया। पानीपत, बहादुरगढ़ और बागपत में भी हालात बेहद चिंताजनक रहे, जहां एक्यूआई 440 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मेरठ, मानेसर और गुरुग्राम जैसे शहर भी 350 के पार पहुंच गए हैं। एनसीआर का लगभग हर प्रमुख इलाका डार्क रेड जोन में शामिल हो चुका है, जो सीधे तौर पर गंभीर स्वास्थ्य खतरे की चेतावनी देता है।

प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर पड़ रहा है। दमा, हृदय रोग, टीबी और सांस से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या अस्पतालों में तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक इस तरह की जहरीली हवा में सांस लेना फेफड़ों और दिल के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। हालात के डर से लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। सड़कों पर आम दिनों की तुलना में कम आवाजाही दिखाई दे रही है और बाजारों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। क्रिसमस और साल के अंत की रौनक पर प्रदूषण ने ग्रहण लगा दिया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार प्रदूषण के पीछे पीएम 2.5 सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आया है, जबकि कुछ इलाकों में पीएम 10 का स्तर भी बेहद खतरनाक बना हुआ है। हवा की रफ्तार बेहद कम होने, तापमान गिरने और नमी बढ़ने के कारण प्रदूषक कण वातावरण में लंबे समय तक टिके हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले तीन से चार दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है, ऐसे में जब तक तेज हवा या बारिश नहीं होती, तब तक राहत की उम्मीद बेहद कम है।

हालात की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आपात बैठक के बाद ग्रैप-4 लागू करने का फैसला लिया। इसके तहत एनसीआर में सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। ट्रकों की एंट्री सीमित कर दी गई है और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी सख्त पाबंदी लगा दी गई है। खुले में कचरा जलाने और धूल फैलाने वाली गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा और दफ्तरों पर भी इसका असर साफ नजर आने लगा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्कूलों को 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश दिए गए हैं। कई सरकारी और निजी कार्यालयों ने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू कर दी है ताकि लोगों की आवाजाही कम हो और प्रदूषण का असर कुछ हद तक घटाया जा सके। एनसीआर में बढ़ता वायु प्रदूषण एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर रहा है कि हर साल सर्दियों में यही हाल क्यों होता है और स्थायी समाधान कब निकलेगा। फिलहाल हालात इतने गंभीर हैं कि साफ हवा लोगों के लिए किसी लग्जरी से कम नहीं रह गई है और पूरा क्षेत्र एक अदृश्य लेकिन जानलेवा संकट से जूझ रहा है।